an>

Title: Need for environment clearance for mining in areas less than five hectares.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27 फरवरी, 2012 को एक आदेश पारित किया और राज्य सरकारों को इस बात का निर्देश दिया कि वÂान 2010 की वन और पर्यावरण मंत्रालय की जो गाइडलाइन बनी हैं ..(व्यवधान) जो ड्राफ्ट रूल्स माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग मिनिस्ट्री ने बनाये हैं ..(व्यवधान) अपूदान खनिजों के लिए, माइनर मिनरल्स के लिए उनकी अनुपालना जब तक नहीं हो ..(व्यवधान) तब तक खानों का नवीनीकरण नहीं किया जाये। ..(व्यवधान) राजस्थान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की उस आदेश की मंशा के अनुरूप अपने नियमों में संशोधन किया ..(व्यवधान) जिला स्तरीय पर्यावरण समितियां बनायी ..(व्यवधान) मेरे प्रदेश में सैंड स्टोन्स की छोटी-छोटी खाने हैं ..(व्यवधान) उन खानों के कलस्टर बनायें ..(व्यवधान) उन खानों के डेवेलपमेंट प्लान बनाकर, उनका अप्रूवल करने के बाद में उनका रिन्यूवल किया गया। ..(व्यवधान) भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने वÂान 2013 में एक नयी अधिसूचना जारी करके निर्देश दिया कि उन छोटी खानों को, नयी खानों को लाइसैंस नहीं दिया जाये। ..(व्यवधान) जब तक वह पर्यावरण की नियमों की पूर्ति नहीं कर लेती। ..(व्यवधान) पांच हेक्टेयर से कम की माइंस के लिए भी एनवायरमेंट क्लीयरैंस लेने की बाध्यता कर दी। ..(व्यवधान) छोटे-छोटे खान मालिकों, जिनके खानों की साइज 30 मीटर से 50 मीटर के बीच हैं ..(व्यवधान) उनके लिए इस तरह के कठोर नियम बना दिये गये। ..(व्यवधान) जबकि ऐसे नियम बनाने की मंशा जो है, सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है, उसकी बिल्कुल नहीं थी। ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, राजस्थान सरकार ने मॉडल गाइडलाइन्स, 2010 के अनुरूप कार्रवाई कर दी थी ..(व्यवधान) उसके बाद भी एम.ओ.ई.एफ. ने, भारत सरकार के वन मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी करके नवीनीकरण पर भी रोक लगा दी। ..(व्यवधान) इसी फ्रम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित किया ..(व्यवधान) उसने आदेश पारित करके सभी खानों के लिए चाहे वह पांच हेक्टेयर से छोटी हैं या बड़ी हैं ..(व्यवधान) सभी खानों के लिए ऐसी बाध्यता उत्पन्न कर दी। ..(व्यवधान) छोटे-छोटे खान मालिक इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ..(व्यवधान) उसके कारण पूरे क्षेत्र में भारी असंतोÂा व्याप्त है। ..(व्यवधान) हजारों-लाखों मजदूर और खान से जुड़े हुए लोग बेरोजगार होने वाले हैं। ..(व्यवधान) उनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है ..(व्यवधान) उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा कर अपील दायर करे। ..(व्यवधान) ऐसे छोटे-छोटे खान मालिकों को और उनसे जुड़े हुए लाखों लोगों जिनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है उनको राहत प्रदान कराने की दिशा में काम करे। ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे, श्री दुÂयंत सिंह, श्री पी.पी.चौधरी और कुँवर पुÂपेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।